



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2004/1 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 22 दिसम्बर, 2004

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-59/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर

संशोधन विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में द्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० प्रार० गजटा,
सचिव।

2004 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 3 नवम्बर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1979 का
15.

2. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (गग) में "इसके अन्तर्गत" शब्दों के पश्चात् "अतिरिक्त या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण. —खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिए जहां किसी होटल में कोई आवास सुविधा, टाइम शेयर करार के अधीन या पैकिज डील करार के अधीन या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अधीन उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें वर्ष में दो गई अवधि के दौरान आवास के उपभोग की सुविधा एक मुश्त संदाय के अन्तर्गत अनुज्ञात की गई है, तो उसे भी 'होटल' समझा जाएगा ;"

(iii) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.—खण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिए जहां उपलब्ध करवाई गई आवास सुविधा टाइम शेयर करार या पैकिज डील करार या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अधीन है जिसमें केवल अनुरक्षण प्रसार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किए गए किसी एक मुश्त संदाय के अतिरिक्त कालिकतः संगृहीत किए गए हैं, तो उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए, प्रभार निम्नलिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) जहां किसी होटल में निम्नलिखित सुविधाओं में से कोई सुविधा

है तो, वस्तुतः उपभोग में लाई गई आवास सुविधा के लिए पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन :—

- (i) स्विमिंग पूल,
- (ii) हेल्थ क्लब,
- (iii) टेनिस कोर्ट,
- (iv) गOLF कोर्स,
- (v) शॉपिंग आरकेड ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, विलास-वस्तु के लिए प्रभारों की गणना, वस्तुतः उपयोग में लाई गई आवास सुविधा के लिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तीन सौ रुपये की दर से की जाएगी।”;

(iv) पद “नए होटल” को परिभाषित करने वाले विद्यमान खण्ड (डड) को (डडड) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

धारा 4 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि जहां होटल में उपलब्ध करवाई गई विलास वस्तु के लिए प्रभार दैनिक आधार पर से अन्यथा संदेय है, तो आवास सुविधा के अधिभोग की कुल अवधि के लिए प्राप्तियों के आवर्त की संगणना एक दिन के लिए अनुपाततः की जाएगी और विलास-वस्तु कर तदनुसार संदत्त किया जाएगा।”।

2004 के अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां। 4. (1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 की धारा 2 के खण्ड (गग) के अधीन अभिव्यक्ति "उप-आवकारी और कराधान आयुक्त" के अन्तर्गत संयुक्त आवकारी और कराधान आयुक्त भी है जबकि विभाग में, अतिरिक्त आवकारी और कराधान आयुक्त भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए उक्त खण्ड (गग) में अतिरिक्त आवकारी और कराधान आयुक्त को भी सम्मिलित करना अनिवार्य समझा गया। इसके अतिरिक्त किसी होटल में टाइस शेयर करार या पैकेज डील करार के विभिन्न तरीकों के अधीन या किसी अन्य प्रणाली के अधीन वर्ष में दी गई किसी अवधि के दौरान एक मुश्त संदाय पर या अनुरक्षण या ऐसे ही प्रभारों के संदाय पर भी विलास-वस्तु उपलब्ध करवाई जाती है परन्तु विलास-वस्तु कर के निर्धारण में एकरूपता नहीं है। इसलिए विद्यमान उपबन्धों को अधिक सुव्यक्त और स्पष्ट बनाने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि सुसंगत उपबन्धों के अधीन उपयुक्त स्पष्टीकरण जोड़ कर होटल और आवास गृहों में विलास-वस्तुएं उपलब्ध करवाने की इन प्रकारताओं के सम्बन्ध में स्पष्टता और पारदर्शिता लाई जाए। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 का संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 5) प्रथम नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित किया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 3 नवम्बर, 2004 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

3. यह विश्लेषक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख , 2004.

वित्तीय जापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS
AND LODGING HOUSES) SECOND AMENDMENT
BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in
Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tax
on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment
Act, 2004.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of
November, 2004.

15 of 1979

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in
Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as
the 'principal Act'),—

Amend-
ment of
section 2.

- (i) in clause (cc), after the words "also include the", the words
"Additional or" shall be inserted;
- (ii) after clause (d), the following Explanation shall be added,
namely:—

*"Explanation.—For the purpose of clause (d) wherever any
accommodation in a hotel is provided under timeshare agree-
ment or under package deal agreement or under any such other
system wherein the facility of availing accommodation during a
given period in a year is allowed under a lump-sum payment,
shall also be deemed to be a 'hotel' ";*

- (iii) after clause (e), the following Explanation shall be added,
namely :—

*"Explanation.—For the purpose of clause (e) wherever
accommodation provided is under timeshare agreement or
under a package deal agreement or under any such other system
wherein only maintenance charges, by whatever name called,
are collected periodically; over and above any lump-sum*

payment made, the charges for luxury provided shall be determined as under, namely :—

(a) Where a hotel is having any of the following facilities, Rs. 500/- per person per day for the accommodation facility actually availed :—

- (i) swimming pool,
- (ii) health club,
- (iii) tennis court,
- (iv) golf course,
- (v) shopping arcade; and

(b) In all other cases, the charges for luxury shall be worked out at the rate of Rs. 300/- per person per day for the accommodation facility actually availed.”; and

(iv) the existing clause (ee) defining the expression “new hotel” shall be renumbered as (eee).

Amend-
ment of
section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that where the charges for luxury provided in a hotel are payable otherwise than on daily basis, then the turnover of receipts for the total period of occupation of accommodation shall be computed proportionately for a day and luxury tax paid accordingly.”.

Repeal of
Ordinance
No. 5 of
2004 and
savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under clause (cc) of section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the expression "Deputy Excise and Taxation Commissioner" includes the Joint Excise and Taxation Commissioner, whereas the Additional Excise and Taxation Commissioners are also working in the department. As such, it was considered essential to include the Additional Excise and Taxation Commissioner as well in said clause (cc). Further, luxury is also provided under different methods like timeshare agreement or package deal agreement or under such other system in a hotel during any given period in a year on a lump-sum payment or only on payment of maintenance or similar charges but assessment of luxury tax lacks uniformity. As such, in order to make the existing provisions more explicit and clear, it was decided to add suitable explanations under relevant provisions to introduce clarity and transparency with regard to these modalities of providing luxury in hotels and lodging houses. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

2. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Ordinance, 2004 (Ordinance No. 5 of 2004) was promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 1st November, 2004, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 3rd November, 2004. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The.....2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-